जिला पथों का उन्नयन, 639.53 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ, 83.60 किलोमीटर राज्य उच्च पथों एवं 5399.84 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण/उन्नयन किया गया।

- वर्ष 2014 में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य उच्च पथों एवं वृहद् जिला पथों के अनुरक्षण हेतु बनाई गई नीति के तहत 2579 करोड़ रुपये की लागत से 9064 किलोमीटर सड़कों के अनुरक्षण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2014 में पटना में बेली रोड अवस्थित जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ तक एलिवेटेड हाई-वे का कार्य, पटना शहर स्थित मीठापुर रोड ओवर ब्रिज से स्टेशन रोड होते हुए चिरैयाटांड पुल तक तथा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के अन्तर्गत गंगा पथ का कार्य तथा गोपालगंज के बिशुनपुर में गंडक नदी पर पुल, आरा-छपरा के बीच गंगा नदी पर पुल, कोसी नदी पर विजयघाट पुल, चकिया-केसरिया-सतर घाट पथ के 27वें किलोमीटर पर पुल तथा गया जिला के गया एवं मानपुर के बीच फल्गु नदी पर 6-लेन पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2014 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) के अन्तर्गत पटना शहर के बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच में चार जंक्शनों (ललित भवन जंक्शन, पुनाईचक चैराहा, हड़ताली मोड़ चैराहा एवं बोरिंग रोड जंक्शन) पर मल्टी अंडरपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड सेक्सन, यू-गर्डर एवं एक्स्ट्रा डोज्ड केबुल स्टेड स्ट्रक्चर के उपयोग के साथ पेमेंट फिनिस्ड रोड, एपरटेनान्सेस, पेडेस्ट्रीयन क्रॉसिंग, साफ्टवेयर कंट्रोल सोलर लाइट, लैन्ड स्केपिंग, इन्टीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम के साथ स्वेप एवं सेपरेटेड यू-टर्न बेस्ड मल्टी सेक्शनल इंटरचेन्ज के निर्माण हेतु 391.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2014 में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत द्वारिका नगर सरफुद्दीन पथ में बूढ़ी गंडक नदी के आथर घाट पर भू-अर्जन कार्य सहित पहुँच पथ का निर्माण कार्य एवं बचाव कार्य सहित उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (35.54 करोड़ रुपये) के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2014 में दरभंगा जिलान्तर्गत नैयत ग्राम के निकट बागमती नदी के पंचकुटिया घाट पर भू-अर्जन कार्य सहित पहुँच पथ का निर्माण एवं बचाव कार्य तथा उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (23.19 करोड़ रुपये) के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2014 में लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के सदायविगहा के पास हरोहर नदी पर भू-अर्जन कार्य सहित पहुँच पथ का निर्माण एवं बचाव कार्य तथा उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (30.78 करोड़ रुपये) के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2014 में लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के सूरजीचक ग्राम के नजदीक हरोहर नदी पर भू-अर्जन सहित पहुँच पथ का निर्माण एवं बचाव कार्य तथा उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (25.87 करोड़ रुपये) के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2014 में राज्य के सुदूर इलाकों को राजधानी पटना से जोड़ने एवं अधिकतम छः घंटे में इस दूरी को तय करने का संकल्प को पूरा किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 510.91 किलोमीटर (649.50 करोड़ रुपये) राज्य उच्च पथों का उन्नयन कार्य, 1213.17 किलोमीटर (2202.21 करोड़) वृहद् जिला पथों का उन्नयन कार्य एवं वृहद् जिला पथों में अवस्थित 102 अदद् (508.43 करोड़ रुपये) Unbridged Gap/क्षतिग्रस्त पुलों/स्कू पाईल पुलों की जगह आर0सी0सी0 पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी, ताकि कम चौड़ाई वाले स्कू पाईल पुलों पर जाम से बचा जा सके एवं भारी वाहनों का आवागमन निर्बाध हो सके।
- वर्ष 2015 में 4952 किलोमीटर पथों को इंटरमीडिएट लेन/2-लेन या उससे अधिक में परिणत किया गया। जिन वृहद् जिला पथों का उन्नयन इंटरमीडिएट लेन में नहीं किया जा सका है, उनपर सतह नवीकरण एवं अन्य मरम्मती का कार्य सम्पन्न किया गया।
- वर्ष 2015 में महत्वपूर्ण मेगा पुलों में अरवल जिला अन्तर्गत अरवल सहार के बीच सोन नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (163.00 करोड़ रुपये), पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत धनहा से रतवल घाट में गंडक नदी के उपर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (358.67 करोड़ रुपये), सहरसा जिलान्तर्गत कोसी नदी के बलुआहा घाट पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल (531.15 करोड़ रुपये), भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया के विजयघाट के समीप कोसी नदी पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल (367.81 करोड़ रुपये) तथा पटना शहर के बेली पथ में शेखपुरा मोड़ एवं जगदेव पथ मोड़ के बीच फ्लाई ओवर का निर्माण (298.66 करोड़ रुपये) किया गया।
- वर्ष 2015 में पटना जिलाधीन पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाई ओवर से चिरैयाटांड फ्लाई ओवर (भाया करबिगहिया) को जोड़ने हेतु पहुँच पथ एवं सर्विस पथ (दोनों तरफ) आदि कार्य सहित लगभग 1128 मीटर लम्बा 4 लेन ऊपरी पुल (फ्लाई ओवर) का निर्माण कार्य कुल 121.86 करोड़ रुपये से करने की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2015 में राज्य में लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के तहत प्रमुख मार्गों का 4-लेन में विकास/निर्माण किया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा जन-निजी भागीदारी के अंतर्गत 1602.74 करोड़ रुपये की लागत से बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुँच पथ के साथ पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 के मोहनियाँ-आरा पथांश का 4-लेनिंग का कार्य (कुल लागत 917.00 करोड़ रुपये) एवं राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-31 के रजौली-बख्तियारपुर पथांश का 4-लेनिंग का कार्य (कुल लागत 817.10 करोड़ रुपये) भी प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में दीघा से दीदारगंज तक पथ (गंगा पथ) (3160.00 करोड़ रुपये) एवं पटना स्थित एम्स से दीघा तक 11.90 किलोमीटर एलिवेटेड कोरिडोर (1289.00 करोड़ रुपये) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- पटना जिला अंतर्गत राष्ट्रीय पथों का निर्माण/उन्नयन के तहत यातायात की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं जनहित में विगत वर्षों में 969.77 करोड़ रुपये व्यय कर 2232 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण/उन्नयन कार्य राज्य निधि से सम्पन्न हुआ।
- जापान इंटरनेशल कंपनी एंड ऑपरेशन एजेंसी संपोषित योजना अन्तर्गत गया-हिसुआ- राजगीर-नालन्दा-बिहारशरीफ खंड का निर्माण कार्य (1408.85 करोड़ रुपये) की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2015-16 में राज्य के सुदूर इलाकों से राजधानी पटना पहुँचने के लिए अधिकतम पाँच घंटों में दूरी तय करने के लक्ष्य के विरुद्ध वृहद् पैमाने पर सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य सहित पुल-पुलियों के निर्माण कार्य का वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के कार्रवाई की गई।
- वर्ष 2015 में राज्य के सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि 15 लाख रुपये या उससे कम है, से संबंधित अंचल स्तर पर वर्षवार कुल कार्यों का 50 प्रतिशत कार्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संवेदकों के लिए आरक्षित करते हुए उक्त कोटि के अन्तर्गत ही प्राप्त निविदा के माध्यम से कार्यों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2015 में पदाधिकारियों/कर्मियों की कार्यक्षमता/दक्षता बढ़ाने एवं आधुनिक तकनीक से अवगत कराने हेतु देश के अन्दर एवं विदेशों में भी प्रशिक्षण दिया गया। अबतक कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं चीन में एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं विश्व बैंक की सहायता से पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया।
- वर्ष 2015 में स्पेशल प्लान (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-BRGF) अंतर्गत 10वीं, 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2042.84 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण (व्यय 3647.62 करोड़ रुपये) किया गया।
- वर्ष 2015 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत 146.94 किलोमीटर की लम्बाई में 7328.46 लाख रुपये व्यय कर पक्का रोड पूर्ण किया गया। 478.79 लाख रुपये लागत से कुल 28 पुल/कलभर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

वर्ष 2015 से 2020 के दौरान किये गए कार्य

- वर्ष 2015-16 में कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक गंगा नदी पर 6 लेन पथ पुल परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के फेज-1 (स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना) के अंतर्गत 206 किलोमीटर चार लेन चौड़ीकरण किया गया।
- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के फेज-2 (पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर) के अंतर्गत 481.44 किलोमीटर चार लेन चौड़ीकरण किया गया।
- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के फेज-3 के अंतर्गत 545.88 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के फेज-4 के अंतर्गत 177 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2017 तक मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित 3995 अदद तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित 1117 अदद योजनाओं को पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2017 में सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के पहलेजा घाट रामसापुर गड्डीपट्टी के बीच गंगा नदी पर कुल 24 सेट पीपा पुल का निर्माण कार्य किया गया।
- वर्ष 2017 में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेजरगंज ढंग पथ में दूसरे किलोमीटर में पहुँच पथ निर्माण कार्य एवं बचाव कार्य सहित 3x21.00 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2017 में चम्पारण जिलान्तर्गत धुमनगर मलदहिया अंजुआ पथ के पहले किलोमीटर में बलोर नदी पर पुराने स्कू पाईल पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2017 में गया जिलान्तर्गत बेलागंज से बराबर (लिंक श्रीपुर पथ) के सातवें किलोमीटर में (2x14.50 मी0) आकार के आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2017 में गया जिलान्तर्गत धनगाई बाजार से बी0बी0 फेसर-सोम से जी0टी0 पथ तक के चेनेज 550 मी0 पर (5x16.00 मी0) आकार के आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2017 में गया जिलान्तर्गत अम्बा-गया पथ (एस0एच0-101) के गया मेडिकल कॉलेज से मथुरापुर खण्ड के 70वें किलोमीटर में मोरहर नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2017 में दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी रैयाम पथ के पाँचवें किलोमीटर में सगुना नदी पर स्कू पाईल पुल के स्थान पर पहुंच पथ निर्माण कार्य एवं बचाव कार्य सहित 5x18.00 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2017 में पटना शहर स्थित मीठापुर आर0ओ0बी0 से स्टेशन होते हुए चिरैयाटांड़ उपरी पुल का एक्जीविशन रोड आर्म का गाँधी मैदान तक विस्तारीकरण कार्य पूर्ण किया गया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA) Phase-I के तहत् राज्य के पाँच जिले औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई एवं मुजफ्फरपुर में 64 अद्द पथ पैकेज (कुल लम्बाई 1038 कि0मी) एवं 41 अद्द पुल के पैकेज का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्राप्त हुई है, जिसमें से 1007.28 किलोमीटर पथांश एवं 35 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण है।
- RCPLWEA Phase-IIके तहत् वर्ष 2019-20 (Batch-I) के तहत रोहतास, नवादा एवं जमुई जिलें में अतिरिक्त 50 अद्द पथ पैकेजों (कुल लम्बाई-590 किलोमीटर) एवं 27 अद्द पुल पैकेज की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 508.67 किलोमीटर पथ एवं 24 पुल का कार्य पूर्ण है।
- वर्ष 2020 में चकिया-केसरिया सत्तरघाट पथ के 27वें किलोमीटर में गंडक नदी पर 9.5 किलोमीटर लंबाई के पहुँच पथ सहित 1440 मीटर लंबाई के उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया गया है।
- वर्ष 2020 में बंगराघाट में राज्य उच्च पथ-74 (मुजफ्फरपुर) एवं राज्य उच्च पथ-90 (सारण जिला) को जोड़ने वाले पथ में गंडक नदी पर 3 लेन के 35 ग 43 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण पूर्ण कराया गया है।

वर्ष 2020 से अबतक किये गए कार्य

- RCPLWEA Phase-III के तहत् वर्ष 2021-22 (Batch-I) के तहत औरंगाबाद, गया एवं बांका जिला में अतिरिक्त 11 अद्द पथ पैकेज (कुल लम्बाई-189 किलोमीटर) एवं 01 अद्द पुल पैकेज में कार्य की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 162.75 किलोमीटर पथ एवं 01 पुल का कार्य पूर्ण है।
- RCPLWEA Phase-III के तहत वर्ष 2022-23 (Batch-II) के तहत औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिला में 28 अदद पथ (कुल लम्बाई-164 किलोमीटर) एवं 13 अदद पुल के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 104.52 किलोमीटर पथ एवं 03 पुल का कार्य पूर्ण है।
- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत Road Requirement Plan-I (RRP-I) के अधीन चिह्नित 05 जिलों यथा, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं जहानाबाद में राष्ट्रीय उच्च पथ सहित कुल 41 परियोजनाएँ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है, जिसमें से 565.47 करोड़ रुपये व्यय कर 666.56 किलोमीटर (राष्ट्रीय उच्च पथ-72.825 किमी, राज्य उच्च पथ- 64.60 किलोमीटर, वृहद् जिला पथ-529.135 किलोमीटर) का कार्य पूर्ण हो गया है।
  Road Requirement Plan-I (RRP-I) के अधीन चिह्नित 06 जिलों यथा, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका एवं मुजफ्फरपुर में चिन्हित 60 मुख्य जिला (MDR) पथों, जिसकी लंबाई 1052.27 किमी है, के उन्नयन/निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2021 में पटना शहर में मीठापुर ऊपरी पुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) ऊपरी पुल वाया आर0 ब्लॉक जंक्शन का पहुँच पथ, रिटेनिंग वॉल, सेवा पथ, पथ जंक्शन, विद्युतीकरण एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्य पूर्ण कराया गया है।
- 321.40 करोड़ की लागत से पटना शहर के बेली रोड पथ में शेखपुरा और जगदेव पथ मोड़ के मध्य ऊपरी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2021-22 में ईपीसी परियोजना अंतर्गत अटल पथ के फेज-1 एवं फेज-2 का कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2021-22 में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत धनहा-रतवल पथ पर अवस्थित धनहाघाट एवं रतवलघाट के बीच गंडक नदी पर नवनिर्मित उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल के दोनों तरफ सम्पर्क पथ एवं उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2021-22 में औरंगाबाद एवं रोहतास जिलान्तर्गत दाउदनगर-नासरीगंज के बीच सोन नदी पर चार लेन उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2021-22 में किशनगंज जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ-31 के 472.30 किलोमीटर से 475.48 के बीच मौजूद उपरी पुल के समानान्तर दूसरे फ्लाई ओवर का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2022-23 में रेल-सह-सड़क पुल दीघा पटना के सड़क मार्ग सारण साइड के पहुँच पथ कार्य किया गया।
- वर्ष 2022-23 में प्रारंभ सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर में डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2022-23 में नालन्दा जिलान्तर्गत सालेपुर-नरसंडा-तेलमर-करौटा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2022-23 में आरा जिलान्तर्गत सासाराम बाईपास पथ बेला से मोकर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2023 में गोपालगंज जिलांतर्गत कटैया बाईपास रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2023 में कटिहार जिलांतर्गत गेराबारी बाईपास रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2023 में अरवल जिलांतर्गत कुर्था बाईपास रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2023 में पटना जिलांतर्गत मीठापुर बस स्टैंड (गेट नं. 2 के निकट) से राष्ट्रीय उच्च पथ-31 वाया विग्रहपुर संजय नगर रोड का निर्माण पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2023 में पटना जिलांतर्गत कंकड़बाग मेन रोड (कुम्हरार) से राष्ट्रीय उच्च पथ-30 तक वाया ट्रांसपोर्ट नगर रोड का निर्माण पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2023 में पटना जिलांतर्गत कंकड़बाग रोड नं. 4 (साईं नेत्रालय के निकट) से राष्ट्रीय उच्च पथ-30 वाया आरएमएस कॉलोनी रोड का निर्माण पूर्ण कराया गया है।
- पटना जिलान्तर्गत कारगिल चौक, गाँधी मैदान से सांईस कॉलेज वाया पीएमसीएच अशोक राजपथ में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- खगड़िया जिलांतर्गत सोनमखी घाट में रोजवर्ड अकादमी से भिरयाही पोखर वाया बछौता बाईपास रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2024 में गया जिलांतर्गत न्यू बाजार बाईपास रोड से राष्ट्रीय उच्च पथ-2 वाया राम मंदिर, डाकबंगला, रमना, शेखपुरा, गुरुकुल रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- वर्ष 2024 में वैशाली जिलांतर्गत टोल प्लाजा राष्ट्रीय उच्च पथ-22 से दौलतपुर बाईपास रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- पटना शहर में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक 4-लेन जे0पी0 गंगा पथ का निर्माण कार्य रू0 3390.00 करोड़ की लागत से प्रगति पर है। दीघा से गायघाट तक एवं जे0पी0 गंगा पथ से पीएमसीएच को Exclusive Connectivity प्रदान करने हेतु भी 4-लेन एलिवेटेड पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। साथ ही गायघाट से कंगनघाट के बीच 12.10 किलोमीटर से 15.50 किलोमीटर तक के पथ का माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 10.07.2024 को लोकार्पण किया गया है। इससे पटना साहिब गुरुद्वारा, पटन देवी मंदिर, न्यू बाईपास सहित आस पास के ईलाकों में आवागमन की सुविधा होगी।
- भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत बिहार राज्य में कुल 554.08 किलोमीटर में निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना सीमावर्ती सात जिलों यथा- पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज से गुजरती है। इस मार्ग रेखण पर कुल 123 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण भी राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है। इसमें से 117 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

Nov. 2024

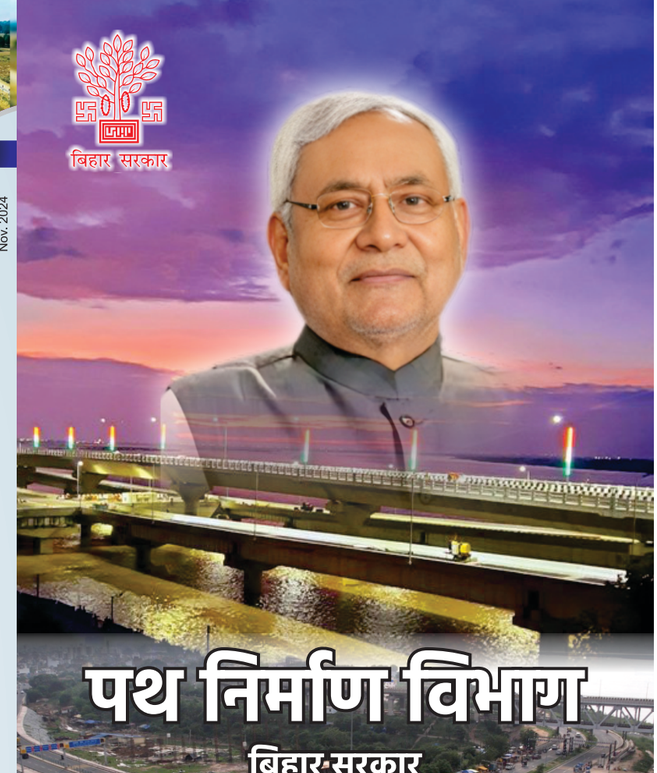

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

पथ निर्माण विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

पथ निर्माण

राज्य के विकास में सड़कों एवं पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी महत्ता की पहचान करते हुए **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में** राज्य में योजनाबद्ध तरीके से सड़क संरचनाओं को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरुप निर्मित करने हेतु विभाग द्वारा मिशन मोड में सड़कों/पुल परियोजनाओं को क्रियान्वित कर मूर्त रुप दिया जा रहा है। पूर्व में यह लक्ष्य रखा गया कि राज्य में सड़कों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को सुदूर क्षेत्र से भी राजधानी, पटना पहुँचने में अधिकतम छः घंटे का समय लगे। जब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया तो लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करते हुए अब इसे पाँच घंटे का रखा गया है।

इसी उद्देश्य से पूरे राज्य में उत्कृष्ट सड़कों, पुल-पुलियों, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण बिहार की आम जनता आज मात्र 5 घंटे में बिहार के किसी कोने से बिहार की राजधानी पटना पहुँचने में कामयाब हो पा रही है। साथ ही अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों एवं पुलों के निर्माण से बिहार में आर्थिक विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवायें, पर्यटन एवं मनोरंजन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शहरीकरण एवं सामाजिक एकता के क्षेत्र में नये आयाम कायम हो रहे हैं। इसके लिए विभाग के बजट में वृद्धि की गई, जहाँ वर्ष 2004-05 में पथ निर्माण विभाग का बजट मात्र 566.468 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 4194.16 करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में पथ निर्माण विभाग का व्यय मात्र 362.174 करोड़ रुपये था, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 17 गुणा बढ़कर 6403.38 करोड़ हो गया है।

आवागमन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ त्वरित निर्माण के लिए विभागीय कार्य-शैली में कई बदलाव किए गये हैं। विभाग द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अभियंताओं को विभिन्न स्तरों पर यहाँ तक की विदेशों में भी प्रशिक्षित कराये जाने का कार्य किया गया है। संवेदकों की कमी को देखते हुए संवेदकों के निबंधन नियमावली का सरलीकरण किया गया। देश के विभिन्न भागों में कार्यशाला का आयोजन कर बड़े-बड़े संवेदकों को बिहार राज्य में आमंत्रित किया गया। राज्य के अन्दर संवेदक भयमुक्त होकर कार्य कर सके, इस हेतु सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। फलस्वरुप बड़े-बड़े संवेदकों द्वारा पथ/पुल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेष रुचि ली गई। स्टैण्डर्ड बिडिंग, ई-टेंडरिंग, डाटा सेन्टर, थर्ड पार्टी गुणवत्ता जाँच, संवेदकों के ऑनलाईन निबंधन, समय से पूर्व कार्य पूर्ण करने पर बोनस एवं विलंब से कार्य पूर्ण करने पर दंड का प्रावधान इत्यादि पहल कर कार्य संस्कृति में बदलाव के साथ पारदर्शिता भी लायी गयी है।

राज्य में विभाग के अधीन वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई 6140.00 किलोमीटर राज्य उच्च पथ की लंबाई 3638.00 किलोमीटर एवं वृहद् जिला पथ की लंबाई 16181.00 किलोमीटर है। वर्ष 2005 में मात्र 51.67 किलोमीटर राज्य उच्च पथ 2-लेन की थी, जबकि वर्तमान में कुल 3638 किलोमीटर राज्य उच्च पथ में से 2588 किलोमीटर दो लेन, 362 किलोमीटर दो लेन से अधिक हैं एवं शेष 747 किलोमीटर दो लेन से कम है जिसे चरणबद्ध तरीके से दो लेन मानक संरचना में उन्नयन की कार्रवाई प्रगति में है।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं यथा, नई ग्रीनफ़ील्ड सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों के उन्नयनीकरण एवं चैड़ीकरण, नदियों पर मेगा पुलों तथा जाम प्रबल स्थानों पर बाईपास/एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के साथ-साथ राज्य उच्च पथों, वृहद् जिला पथों एवं पथों के अनुरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है।

सड़कों के त्वरित मरम्मती एवं दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु मोबाईल रोड एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गयी है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पथों को 72 पैकेजों में बाँटा गया है, जिसके लिए अलग-अलग डेडिकेटेड 72 रोड एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है।

बेहतरीन कार्य प्रणाली के तहत पथ संधारण लोक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा व्हाट्सएप की व्यवस्था, जीपीएस बेस्ड रोड एम्बुलेंस का ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग, ऑनलाईन मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट सिस्टम, मुख्यालय स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना एवं ठेकेदारों का निबंधन हेतु e-Registration की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पथ में हुए दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पथ नेटवर्क में अवस्थित PMU (Petrol Maintenance Unit) को आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यालय से त्वरित निदेश दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही मोबाईल ऐप के माध्यम से पथ की खराबियों का वास्तविक काल अनुश्रवण के साथ-साथ क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा निर्धारित निरीक्षण चक्र सुनिश्चित कराया जा रहा है।

5 किलोमीटर से अधिक दूरी की नई सड़क परियोजनाओं में डिजाइन स्टेज रोड सेफ्टी ऑडिट एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमिटी के द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु निर्गत निदेश का अनुपालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अबतक 159 ब्लैक स्पॉट पर संरचनात्मक सुधार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी पथों में सड़क सुरक्षा अंकेक्षण के सभी सुझावों यथा-जंक्शन उन्नयन, दुर्घटना प्रबल स्थानों पर यातायात शांत करने के उपाय, रोड साईनेज, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा संकेतक चिह्न एवं रंबल स्ट्रीप आदि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके। वाहनों के तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा मोबाईल स्पीड रडार गन की व्यवस्था जे.पी. गंगा पथ सहित कई जगहों पर की गई है।

वर्ष 2005 से 2010 के दौरान किये गए कार्य

- वर्ष 2006 में पथ निर्माण का कार्य 729 करोड़ रुपये की लागत से आरंभ किया गया।
- वर्ष 2006 में कुल 7714 किलोमीटर वृहद् जिला पथ में से 4000 किलोमीटर के चैड़ीकरण तथा मजबूतीकरण का कार्य 1572 करोड़ रुपये की लागत से कराने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त 334 करोड़ रुपये की लागत से 533 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की परियोजनाएँ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF) के अन्तर्गत ली गयी।
- वर्ष 2006 में राज्य में भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया गया, जिसके कारण बाहर की बड़ी कम्पनियाँ और ठेकेदार राज्य में निर्माण कार्य करने को इच्छुक हुए।
- विगत वर्षों में जहाँ सभी श्रेणी के पथों के उन्नयन हेतु प्रतिवर्ष मात्र 15 से 20 करोड़ रुपये योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाते थे, वहीं इस सरकार ने वर्ष 2006 में केवल वृहद् जिला पथों के लिये 678 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त नाबार्ड, केन्द्रीय सडक निधि तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण योजना के लिये 167.65 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये।
- वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने पूर्व से घोषित 2045 कि0मी0 राजकीय उच्च पथ के अतिरिक्त 1054 किलोमीटर पथों को राज्य उच्च पथ घोषित किया।
- राष्ट्रीय उच्च पथों के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त राशि पूर्व में पूर्णतया व्यय नहीं की जाती थी। पहली बार 2006 में राज्य सरकार द्वारा पूरी राशि का व्यय किया गया।
- वर्ष 2006 में पटना शहर के पथों के सर्वांगीण विकास के लिए पटना रोड्स प्रोजेक्ट का गठन किया गया, जिसके अन्तर्गत करीब 150 करोड़ रुपये की लागत पर शहर के प्रमुख पथों का चौड़ीकरण, फुट-पाथ, ड्रेनेज तथा सेन्ट्रल वर्ज के साथ करने का प्रावधान किया गया।
- दूरगामी इलाकों में पुल के अभाव में ग्रामीण जनता को सम्पर्कता में कठिनाई को देखते हुए, इसके निदान हेतु "मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना" वर्ष 2006 में प्रारंभ की गयी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2006 के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
- वर्ष 2006 में पुल प्रक्षेत्र में 125 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी। साथ ही वर्षों से लम्बित चले आ रहे 15 पुलों का निर्माण कार्य 130 करोड़ रुपये की लागत से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्ण कर लिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 773 किलोमीटर तथा 2007-08 में 360 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का उन्नयन पूर्ण किया गया। विगत वर्षों में राष्ट्रीय उच्च पथों का इतने बड़े पैमाने पर उन्नयन कभी नहीं हुआ था।
- पहली बार वर्ष 2007 में राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उच्च पथों के रख-रखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से आवंटन दिया गया।
- वर्ष 2007 में सभी राज्य उच्च पथों को आधुनिक मानकों के अनुसार दो लेन हाईवे में बदलने का कार्य प्रारंभ हुआ।
- वर्ष 2007 में 620 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2007 में 1054 किलोमीटर घोषित नये राज्य उच्च पथ को दो लेन हाईवे में उन्नयन का कार्य एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करने हेतु कार्रवाई की गयी।
- राज्य के दूर दराज विशेषकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत विभिन्न पथों पर वृहद्/लघु पुलों के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 में 400 करोड़ रुपये की निधि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड तथा जिला प्रशासन को आवंटित की गई।
- वर्ष 2007 में गंगा नदी पर आरा- छपरा के बीच पुल, बख्तियारपुर-पटोरी के बीच पुल, पश्चिमी चंपारण-गोपालगंज के बीच और सहरसा-दरभंगा के बीच गंडक नदी तथा कोशी नदी के बीच पुल बनाने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2007 में कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए वर्क प्रोग्राम का निर्धारण किया गया। समय से पहले कार्य पूर्ण करने पर बोनस एवं विलम्ब के लिए पेनाल्टी का प्रावधान किया गया। कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक कम्प्यूटराईज्ड मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु मुख्यालय में डाटा सेन्टर की स्थापना की गई।
- वर्ष 2007 में निबंधन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।
- वर्ष 2007 में इक्यूपमेंट बैंक की स्थापना की गई, जो कार्यों को त्वरित गति से निष्पादन करने के लिए संवेदकों को उचित भाड़े पर प्लांट एवं मशीनरी उपलब्ध कराती है।
- वर्ष 2007 में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी जांच की व्यवस्था की गई। पथ कार्यों के लिए इन्टीग्रेटेड इमप्रूवमेंट कम परफॉरमेंस बेस्ड मेंटेनेन्स का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2007 में मुख्यालय सहित सभी कार्य प्रमंडलों का कम्प्यूटरीकरण किया गया।
- वर्ष 2008-09 तक 2073 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2008 में 1880 किलोमीटर नये राज्य उच्च पथ घोषित किये गये।
- वर्ष 2008 में राज्य के अधीन 6 प्रमुख मार्गों का 4 लेनिंग कार्य जन निजी भागीदारी के माध्यम से करने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी (IDFC) एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एण्ड फायनेंसियल सर्विस (IL & FS) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2008 में कार्यों की गुणवत्ता विशिष्टि के अनुसार नहीं होने पर उनको स्क्रैप कर संवेदक के व्यय पर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया और उसका क्रियान्वयन किया गया।
- वर्ष 2008 में ई-टेन्डरिंग की व्यवस्था तथा 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि की निविदा हेतु स्टैन्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट लागू की गई।
- वर्ष 2008 में 21.16 करोड़ की लागत पर झौआ पुल (कटिहार जिला), 5.52 करोड़ की लागत पर खुरी पुल (नवादा जिला), 20.39 करोड़ की लागत पर डुब्बा पुल (सीतामढ़ी जिला), 2.32 करोड़ की लागत पर रामडिहरी पुल (भोजपुर जिला) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2008 में सोन नदी पर अरवल-सहार पुल (98.5 करोड़), करेह नदी पर लरझा घाट पुल (29.54 करोड़), कंकड़बाग फ्लाईओवर (30.34 करोड़), सकरी नदी पर राजगीर-गिरियक पुल (34 करोड), गंडक नदी पर चकिया, बड़ा गोविंद मधुबन पुल (19.98 करोड़), पंचाने नदी पर राजगीर गिरियक पुल (19.73 करोड़), कमला नदी पर रसियारी घाट पुल (19.00 करोड़), किउल नदी पर साम्हो दियरा पुल (19.66 करोड़) का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2009 में पथ कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना की गई।
- वर्ष 2009 में कुल 788.00 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्य निधि से उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2009 में पटना-गया-बोधगया (राष्ट्रीय उच्च पथ-83) एवं गया-राजगीर- बिहारशरीफ (राष्ट्रीय उच्च पथ-82) को 4 लेन में उन्नयन करने हेतु जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल (जाइका) द्वारा वित्त सम्पोषण पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त की गई।
- वर्ष 2009 में नव घोषित राज्य उच्च पथों में से 820 किलोमीटर को एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 2-लेन में परिणत करने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2009 तक कुल 2,248.00 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2009 में पटना में लोक नायक सेतु, बहादुरपुर रोड ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) एवं सुल्तानगंज रोड ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 580.84 करोड़ रुपये की लागत की 20 अदद रोड ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2009 में गोपालगंज के बिशुनपुर में गंडक नदी पर पुल, अरवल-सहार के बीच सोन नदी पर पुल, सहरसा-दरभंगा के बीच कोसी नदी पर बलुआहा घाट पुल, बगहा-धनहा के बीच गंडक नदी पर रतवल घाट पुल तथा सीतामढ़ी-शिवहर में बागमती नदी पर पिपराही एवं मांडर घाट पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2009 में 25 लाख रुपये से अधिक लागत की योजनाओं की निविदा के लिए ई-टेन्डरिंग की शुरुआत की गई।
- वर्ष 2009 में इण्डियन रोड कांग्रेस का प्लैटिनम जुबली सत्र का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2009 में मुख्यालय में ऑनलाईन टॉल फ्री हेल्पलाईन (18003456161) एवं पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता हेतु मोबाइल इंस्पेक्टर, ऑनलाईन मॉनिटरिंग और इन्फॉर्मेशन कियोस्क की स्थापना की गई।
- वर्ष 2009 में लोहिया सेतु (भागलपुर), लाभा पुल (कटिहार), लोकनायक सेतु (पटना), कंकड़बाग फ्लाई ओवर (पटना), वीर कुंवर सिंह सेतु (आरा) तथा शिवहर-मीनापुर-झपहा पथ के पहले, नौवें, दसवें एवं पन्द्रहवें किलोमीटर में पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2009 में शहरी योजनान्तर्गत बोरिंग रोड से कुर्जी मोड़ तक क्रंकीट पथ (PQC), कंकड़बाग पुरानी बाईपास पथ, बोरिंग कैनाल पथ, आशियाना - दीघा पथ इत्यादि पथों का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2009 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल निर्माण कार्य के अतिरिक्त भवन, सिंचाई, पथ, इवेन्ट मैनेजमेंट आदि कार्यों का सम्पादन किया गया।
- वर्ष 2008-09 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का टर्न ओवर रुपये 42.62 करोड़ (वर्ष 2004-05) से बढ़कर रुपये 768 करोड़ हो गया।लाभ की स्थिति में रहने के कारण वर्ष 2008 में कोसी नदी के विपदा से निपटने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में निगम द्वारा रुपये 20 करोड़ का अंशदान तथा वर्ष 2009 में भी रुपये 20 करोड़ का अंशदान दिया गया।
- वर्ष 2009 में संवेदक निबंधन की प्रक्रिया का सरलीकरण, आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर निबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
- वर्ष 2010 में 1657 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्य निधि से उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2010 में पूर्व घोषित 2.035 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत उन्नयन किया गया।

  अब तक 2031 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का 2-लेन में उन्नयन कार्य राष्ट्रीय सम विकास योजना के अधीन क्रियान्वित किया गया।
- वर्ष 2010 में नव घोषित राज्य उच्च पथों में से 820 किलोमीटर को बिहार स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम (BSHDP)-1 के अन्तर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त कर 2-लेन में परिणत करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2010 में स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम (BSHDP)-2 के अन्तर्गत अन्य 6 राज्य उच्च पथों के उन्नयन हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक से 300 मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति प्राप्त की गई।
- वर्ष 2010 में अति महत्वकांक्षी राज्य उच्च पथ सं. 78 (बिहटा सरमेरा) का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2010 तक कुल 5,585 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2010 तक मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत 1,671 योजनाएँ पूर्ण की गई।
- वर्ष 2010 में मुख्यालय स्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया गया।
- वर्ष 2010 में संविदा विवाद के त्वरित निष्पादन हेतु मध्यस्थता न्यायाधिकरण Arbitration Tribunal का गठन किया गया।
- वर्ष 2010 में पटना शहर में आधुनिक पार्किंग की व्यवस्था की गई।
- वर्ष 2010 में कुल रुपये 739.31 करोड की लागत पर 25 अदद रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) की योजना स्वीकृत की गयी जिसमें 7 रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.)का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त 544 करोड़ की लागत से 12 अदद रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) के निर्माण की स्वीकृति रेलवे मंत्रालय से प्राप्त की गयी।
- बख्तियारपुर-पटोरी के बीच गंगा नदी पर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के आधार पर पुल हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त की गयी।
- आरा-छपरा के बीच गंगा नदी पर तथा कोसी नदी पर विजयघाट पुल की स्वीकृति राज्य निधि से प्रदान की गयी।

वर्ष 2010 से 2015 के दौरान किये गए कार्य

- राज्य के सुदूर एवं दुर्गम जगहों से राज्य की राजधानी पहुँचने में अधिकतम छः घंटे लगें, इसी के अनुरुप आधारभूत संरचना निर्माण अन्तर्गत् 392.49 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्यनिधि से उन्नयन, 140.70 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का उन्नयन तथा 1004.06 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत् 910 योजनाएँ पूर्ण किये गये।
- वर्ष 2011 में 392.49 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्य निधि से उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2011 में पूर्व घोषित 140.70 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत् उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2011 में कुल 1,004.06 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2011 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा क्षतिग्रस्त डुमरी घाट पुल के स्थान पर स्टील पाइप पुल का निर्माण पूर्ण किया गया।
- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा जनवरी, 2011 से सितम्बर, 2011 तक 83 स्कू पाईल पुल, 2 बॉक्स कल्वर्ट, 180 रिइंफोरस्ड सिमेंट कंक्रीट (RCC) पुल, 2 रोड ओवर ब्रिज, 3 पार्क तथा 20 फ्लड शेल्टर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2012 में किशनगंज के कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य के सुदूर इलाकों को राजधानी पटना से जोड़ने एवं अधिकतम छः घंटे में इस दूरी को तय करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- वर्ष 2012 में राज्य के प्रवेश मार्गों यथा, डोभी (गया), रजौली (नवादा), कर्मनाशा (कैमूर), जलालपुर (गोपालगंज), दालकोला (पूर्णियाँ) में समेकित जाँच चौकियों का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2012 में पटना अवस्थित बेली रोड पर जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ तक ऐलिवेटेड हाईवे का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2012 में 184.01 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2012 में पूर्व घोषित 183.40 किलोमीटर राज्य उच्च पथों को राष्ट्रीय सम विकास तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित योजनान्तर्गत उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2012 में कुल 1,291.62 किलोमीटर वृहद् जिला पथों का उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत 612 योजनाएँ पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2012 में 30 वृहद् पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2012 में जन निजी भागीदारी (PPP) के अन्तर्गत बख्तियारपुर-ताजपुर (समस्तीपुर) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण, आरा-मोहनियाँ पथ (राष्ट्रीय उच्च पथ-30) में 4-लेनिंग का कार्य तथा रजौली-नवादा बिहारशरीफ बख्तियारपुर पथ (राष्ट्रीय उच्च पथ-31) में 4-लेनिंग का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में 'राज्य के सुदूर इलाकों को राजधानी पटना से जोड़ने एवं अधिकतम छः घंटे में सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने का लक्ष्य' के अंतर्गत 1296.93 किलोमीटर वृहद् जिला पथों, 199.03 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों, 31 किलोमीटर राज्य उच्च पथों एवं 7796.55 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण/उन्नयन किया गया।
- राज्य में निर्मित सभी सड़कों के अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सभी पथों का नियमित एवं उत्कृष्ट संधारण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने "बिहार पथ आस्तियाँ दीर्घकालीन संधारण नीति 2013" बनाई गई।

  वर्ष 2013 में पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output&Performance Based Road Assets Maintenance Contract) प्रणाली के तहत बिहार राज्य के 9064.318 किलोमीटर वृहद् जिला पथों एवं राज्य उच्च पथों के संधारण कार्य कुल 2579.17 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्राप्त की गई।

  "बिहार पथ आस्तियाँ दीर्घकालीन संधारण नीति 2013" के तहत प्रथम चरण में वर्ष 2013 से 2018 तक कुल 9064 किलोमीटर पथों का पाँच वर्षीय दीर्घकालीन संधारण सफलतापूर्वक किया गया।

  प्रथम चरण के अनुभवों के आधार पर द्वितीय चरण में वर्ष 2019 से 2026 तक की अवधि के लिए राज्य के कुल 13064 किलोमीटर पथों का दीर्घकालीन संधारण सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि राज्य की जनता को लगातार अच्छी सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके। अबतक 8764.63 किलोमीटर पथों का दीर्घकालीन संधारण किया जा चुका है।
- वर्ष 2013 में कमला नदी पर गंडौल (सहरसा जिला) से बिरौल के पास हाथीकोठी (दरभंगा जिला) उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण (332 करोड रुपये), पटना में मीठापुर आर.ओ.बी. से स्टेशन होते हुए चिरैयाटांड़ ऊपरी पुल एवं एक्जीविशन रोड आर्म का विस्तारीकरण (167.85 करोड़ रुपये), गोपालगंज में गंडक नदी के बंगरा घाट पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (508.97 करोड़ रुपये), सुल्तानगंज (भागलपुर जिला) एवं अगुवानी घाट (खगड़िया जिला) के बीच गंगा नदी पर 4 लेन उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण (1710.77 करोड़ रुपये), औरंगाबाद एवं रोहतास जिलान्तर्गत दाउदनगर-नासरीगंज के बीच सोन नदी पर उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण (619.28 करोड़ रुपये), अररिया जिलान्तर्गत नूना नदी पर (इंडो नेपाल बॉर्डर पथ के) मीरगंज रेलवे क्रासिंग से धबेली पथ पर उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण(75.95 करोड़ रुपये), मीनापुर प्रखंड (मुजफ्फरपुर जिला) बूढ़ी गंडक नदी पर कोठरिया घाट पर उच्चस्तरीय आर.सी.सी.पुल का निर्माण (33.00 करोड़ रुपये), (मुजफ्फरपुर जिला) बूढ़ी गंडक नदी पर गंगत्रात्रा मिश्रा कॉलेज के पास आर.सी.सी. पुल का निर्माण (43.3 करोड़ रुपये) इत्यादि वृहद् पुलों की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2013 में वृहद् सड़क परियोजनाओं के निर्माण के तहत दीघा-दीदारगंज लोकनायक गंगा पथ एवं एम्स - दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर की क्रमशः 3160 करोड़ रुपये एवं 1279 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण की स्वीकृति दी गई एवं कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में राज्य में कर-अपवंचना को नियंत्रित करने हेतु राज्य के सीमावर्ती स्थानों में पाँच जाँच-चैकियों यथा- डोभी (गया), रजौली (नवादा), कर्मनाशा (भभुआ), जलालपुर (गोपालगंज) एवं दालकोला (पूर्णियाँ) में चालू की गई।
- वर्ष 2013 में पटना में गंगा नदी के किनारे 'लोकनायक गंगा पथ' (दीघा से दीदारगंज, लम्बाई-21.5 किलोमीटर) के निर्माण कार्य हेतु 2000 करोड़ रुपये का ऋण हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) से प्राप्त तथा परियोजना के निर्माण पर कुल 3160 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरीडोर (लम्बाई 11.9 किलोमीटर) का कार्य आरंभ (प्रशासनिक स्वीकृति 1289.00 करोड़ रुपये) किया गया।
- राज्य के सुदूर इलाकों को राजधानी पटना से जोड़ने एवं अधिकतम छः घंटे में सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने के राज्य सरकार के लक्ष्य के तहत गत एक वर्ष (2013-14) में 946.25 किलोमीटर वृहद्